

संख्या:- / XXIX-2 / 2025 / E-52641

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-02

देहरादून, दिनांक:

अक्टूबर, 2025

विषय: Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2025-26 Part-I (Untied) के अन्तर्गत मसूरी पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना (पुनरीक्षित प्राक्कलन) हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Uttarakhand, दिनांक 19 अगस्त, 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment Part- I (Untied) के अन्तर्गत मसूरी पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 2093.00 लाख (₹ बीस करोड़ तिरानबे लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2- इस संबंध में वित्त अनुभाग-01, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-325633/E-87705 /XXVII(1)/2025, दिनांक 27 अगस्त, 2025 एवं आपके कार्यालय के पत्र संख्या-211/नागर अनुभाग-मसूरी प०पे०यो०/02, दिनांक 21.02.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मसूरी पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन ₹ 16601.12 लाख पर व्यय वित्त समिति (नियोजन विभाग) द्वारा संस्तुत/परीक्षित लागत ₹ 16415.42 लाख (₹ एक सौ चौंसठ करोड़ पन्द्रह लाख बयालीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रश्नगत योजनान्तर्गत विभिन्न शासनादेशों के द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 14446.00 लाख को कम करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment Part- I (Untied) Additional Allocation के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अनुमोदित ₹ 13.8138 करोड़ (₹ तेरह करोड़ इक्यासी लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) उपरोक्त धनराशि विषयगत कार्य हेतु Scheme for Special Assistance to the State for Capital Investments (SASCI) 2025-26 Part I (Untide) Additional Allocation) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ऋण के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही है।
- (ii) उक्तानुसार अनुमोदित/स्वीकृत धनराशि से ही कार्य को समयबद्ध/गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं आंगणन का पुनरीक्षण किसी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
- (iii) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग कर लिया गया हो।
- (iv) उक्त योजनाओं हेतु धनराशि को व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा अन्य शासनादेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 एवं अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- (v) संबंधित कार्य हेतु अनुबन्धित संस्था को उनके साथ हुए अनुबन्ध/एमओयू में भुगतान निहित शर्तों के अनुसार आवश्यकतानुसार ही कार्य की भौतिक प्रगति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
- (vi) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों पर अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इन योजनाओं/कार्यों हेतु पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत की कार्य कराया जायेगा।
- (vii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मदवार व्यय विवरण GFR-2017 के फार्म-12B के प्रारूप पर भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- (viii) स्वीकृत की गयी धनराशि उसी योजना पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। योजना की स्वीकृति के मूल शासनादेश में निहित अन्य समस्त शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
- (ix) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उक्त योजना की सम्पन्न व्यय-वित्त समिति की बैठक दिनांक 03.09.2025 के कार्यवृत्त (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित समस्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 'अनुदान संख्या-07' के लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य भवन-26-विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य (SASCI)-00-के मानक मद '53-वहद निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

3- धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन आई०डी० संलग्न से आवंटित की जा रही है। धनराशि के उपयोग हेतु शासनादेश संख्या-I-287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1) 2025, दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- यह आदेश वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित संख्या-I/338484/2025, दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

Digitally signed by
Apurva Pandey
Date: 24-10-2025
12:31:31

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव

संख्या:- (1)/XXIX-2/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-01/2, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
9. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 24-10-2025
12:37:30

(डी०एम०एस० राणा)
संयुक्त सचिव